>

Title: Alleged open violation of process for formation of new States in the country under article 3 of the Constitution of India and the resultant threat being posed to a religious historical heritage site.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही लोक महत्व के प्रश्न पर अपनी बात सदन में बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के संविधान संशोधन-3 में राज्यों के विभाजन एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रदत्त है लेकिन अभी राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने फैसला किया कि उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटा जाए। बड़े ही आनन-फानन में बीस करोड़ आबादी वाला जो प्रदेश है उसको मात्र 16 मिनट में प्रस्ताव कर के केन्द्र को भेजा जो पूरी तरह से राजनैतिक स्टंट के तहत काम किया गया है। जबकि संविधान में यह प्रदत्त है कि कैबिनेट का फैसला हो और वह राष्ट्रपति के पास जाए। राष्ट्रपति राज्यों की समय-सीमा निर्धारित कर के प्रस्ताव मंगाए और दोनों सदनों में चर्चा होने के उपरान्त, राष्ट्रपति की सहमति से राज्यों का पुनर्गठन होता है लेकिन उल्टा हो रहा है। इसलिए सभापति महोदय, आप के माध्यम से मैं चाहूंगा कि राज्य में डिक्टेटरशीप है, कानून-व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और भ्रष्टाचार की घटनाओं के छिपाने के लिए राज्य के बंटवारे का जो पासा फेका गया है, यह एक तरीके से अंग्रेजों की तरह राज्य को बांटो और शासन करो की नीति उस ने अपनाई है। बहुत से लोगों का अपने उस क्षेत्र से जो गौरव-गरीमा और अपनत्वपन है। वहां की भौगोलिक स्थितियों को अगर देखा जाए, वहां की प्राकृतिक संपदा को अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बयां करती हैं। जैसे अगर पूर्वांचल में राज्य को बढ़ा दिया जाएगा तो वहां पर केवल दबंग प्रवृति के लोगों का ही शासन होगा। हरित प्रदेश की मांग एक छोटे से तबके में किया गया। वहां पर एक जाति विशेष के लोगों का अधिपत्य होने की संभावना है। मध्य क्षेत्र पूरी तरह से विकसित है लेकिन अगर बुंदेलखण्ड का इलाका लिया जाए तो मात्र छः-सात जिले का प्रदेश कैसे बन सकता है? इसके लिए मध्यप्रदेश को तोड़िए। मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड को भरपूर बिजली मिल रही है। वह उत्तर प्रदेश में जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि केवल वोट की राजनीति को देखते हुए जिस प्रकार अपनी काली करतूत को छिपाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है, उसे तत्काल निरस्त करके यहां की जो प्रक्रिया है, जन-भावनाओं का कद्र करते हुए राज्यों का बंटवारा किया जाए। समाजवादी पार्टी इस राज्य के बंटवारे का पुरजोर विरोध करती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।